17.02 hrs.

STATEMENT BY PRIME MINISTER

Prime Minister's recent visit to Germany,

St.Petersburg, Evian and China

Title: Statement made by the Prime Minister regarding his recent visit to Germany, St. Petersburg, Evian and China.

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : महोदय, पिछले दो महीनों में मुझे जर्मनी, रूस, फ्रांस और चीन की अपनी यात्रा के दौरान विश्व के कई नेताओं से मिलने का अवसर मिला।

मैंने दिनांक 27 से 30 मई तक जर्मनी की यात्रा की। उसके बाद, मैं राट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर सेंट पीटर्सबर्ग के त्रिशताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए वहां गया। तत्पश्चात् मैं राट्रपति शिराक के निमंत्रण पर एवियान में जी-8 देशों की विस्तृत वार्ता में शामिल हुआ। दिनांक 22 जून से 27 जून तक मैंने अलग से चीन की यात्रा की।

जर्मनी और चीन की मेरी यात्राएं द्विपक्षीय थीं जबकि रूस और फ्रांस की यात्रा महत्वपूर्ण घटनाओं के उपलक्ष्य में थी, जिनमें केवल चुनिंदा देशों को ही आमंत्रित किया गया था। ये सभी यात्राएं यूरोप और एशिया के प्रमुख देशों के साथ हमारी चलती हुई बातचीत तथा अंतर्राट्रीय मामलों में भारत के बढ़ते हुए महत्व की मान्यता को दर्शाती हैं। मेरी इन यात्राओं से इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और प्रमुख अंतर्राट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दृटिकोण को स्पट करने का मौका मिला। ऐसी यात्राओं से हमें अंतर्राट्रीय समुदाय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दूसरे देशों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद मिलती है।

जर्मनी की मेरी यात्रा चांसलर श्रोएडर के निमंत्रण पर थी जो उन्होंने अक्तूबर 2001 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान मुझे दिया था। जर्मन नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने और उनमें तेजी लाने के बारे में मेरी उपयोगी बातचीत हुई। हमने क्षेत्रीय और अंतर्राट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का विस्तार से आदान-प्रदान किया। जर्मनी का मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व स्तर पर दृढ़तापूर्वक कार्रवाई की जानी चाहिए चाहे वह कहीं भी हो और किसी के भी विरूद्ध चलाया गया हो।

भारत और जर्मनी, दोनों ही व्यापार और निवेश संबंधों में और तेजी लाने के इच्छुक हैं। मैंने भारत में निवेश के अवसरों तथा भारत और जर्मनी के बीच अनेक अनुपूरक पहलुओं पर प्रकाश डाला जिनसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को अधिक बढ़ावा मिलता है। मुझे अनेक जर्मन सांसदों, व्यापार प्रतिनिधियों तथा भारत-विद्याशास्त्रियों से मिलने का मौका भी मिला। म्यूनिख में मेरी बवेरिया के मंत्री-अध्यक्ष एडमंड स्टोइबर के साथ लाभप्रद बातचीत हुई।

जर्मनी जो यूरोपीय संघ में हमारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्ताकारों में से एक है तथा जो जी-8 देशों का सदस्य और इस समय सुरक्षा परिाद का सदस्य भी है, के साथ अपने लगातार बढ़ रहे उच्च-स्तरीय संबंधों को हम महत्व देते हैं। प्रति वा शिखर बैठकें आयोजित करने के हमारे निर्णय के अनुरूप हम अगले वा चांसलर श्रोएडर के भारत आगमन की प्रतिक्षा में हैं।

सेंट पीटर्सबर्ग का 300वाँ वागांठ समारोह शानदार एवम् प्रभावशाली ढंग से मनाया गया। इस विशेा समारोह के लिए भारत को आमंत्रित करना भारत तथा रूसी संघ के बीच घनिठ स्ट्रेटेजिक संबंधों का द्योतक है। यह भी कहना उचित होगा कि इस समारोह में विश्व के प्रमुख नेताओं की इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी रूस के महत्व तथा अंतर्राट्रीय स्तर पर राट्रपति पुतिन के सम्मान की प्रतीक थी।

सेंट पीटर्सबर्ग की मेरी यात्रा के दौरान मुझे राट्रपति पुतिन, फ्रांस के राट्रपति शिराक, चीन के राट्रपति हू जिन्ताओ तथा ब्रिटेन के प्रधान मंत्री टोनी ब्लेयर के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने का अवसर मिला। संयुक्त राज्य अमेरिका के राट्रपति बुश से भी मेरी अनौपचारिक बातचीत हुई।

राट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात में हमने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राट्रीय हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। हम, दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। राट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और गहरा बनाने की रूस की प्रतिबद्धता को दोहराया। वार्िक शिखर सम्मेलन की हमारी सामान्य प्रक्रिया के अमुरूप, मुझे आशा है कि मैं रूस का निकट भविय में द्विपक्षीय दौरा करूंगा।

जी-8 देशों के साथ व्यापक बातचीत के लिए कुछ चुने हुए विकासशील देशों को आमंत्रित करने की पहल के लिए मैंने राट्रपति शिराक को धन्यवाद दिया। बहुध्रुवीय ि वश्व के महत्व पर हमारी समान समझ थी जिसके लिए संयुक्त राट्र का पुनर्गठन करना जरूरी माना गया।

प्रधान मंत्री ब्लेयर के साथ हुई बातचीत में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के स्तर पर संतोा व्यक्त किया। प्रधान मंत्री ब्लेयर ने हमारी महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं के प्रति सं वेदनशीलता और समझ-बूझ दर्शाई।

चीन के राट्रपति हू जिन्ताओ के साथ मेरी मुलाकात में, उन्होंने कहा कि चीन का नया नेतृत्व भारत के साथ मित्रता बढ़ाने पर बहुत बल देता है। हम इस बात पर सहमत हुए कि चीन और भारत, जो विश्व की कुल आबादी का एक तिहाई भाग है, को मिलकर प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए ताकि 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाया जा सके।

भारत उन 14 विकासशील देशों में से एक था जिन्हें एवियान में जी-8 देशों की विस्तृत वार्ता में आमंत्रित किया गया। इस वार्ता में स्वतंत्र रूप से तथा खुलकर बातचीत हुई जिसमें विभिन्न आर्थिक, विकास, पर्यावरण और सुरक्षा संबंधी तथा अन्य मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं पर प्रकाश डालने का मौका मिला।

मैंने अपने भााण में, सहस्त्राब्दि विकास दौर के निार्कों पर सार्थक अनुवर्ती कार्रवाई करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया जिससे एक ऐसी विश्व-व्यापार व्यवस्था बनाई जा सके जो विकास को बढ़ावा दे सके। मैंने मौजूदा प्रतिबद्धताओं का पालन करने तथा विशेाकर अल्प-विकसित देशों में विकास हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन पैदा करने के नए विचारों की जांच करने की जरूरत पर बल दिया। मैंने सुझाव दिया कि यद्यपि क्योटो प्रोटोकोल की पुटि नहीं हो पाई है, फिर भी, जैसा कि प्रोटोकोल में व्यवस्था की गई है, प्रोत्साहनों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के जरिए स्वच्छ ऊर्जा विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों को उनके जैव-वि विधता संसाधनों तथा उनके परंपरागत ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए समुचित प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए। मैंने इस कटु सत्य की ओर ध्यान दिलाया कि यदि इन क्षेत्रों में तत्काल और स्पट प्रगति नहीं होती तो विकासशील देशों में आर्थिक उदारीकरण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण पर्यावरण उपायों के लिए राजनैतिक समर्थन जल्दी ही ि वखंडित हो जाएगा।

जी-8 शिखर बैठक के अवसर पर मुझे ब्राजील तथा मैक्सिकों के राट्रपतियों से मिलने का अवसर मिला। दोनों ही राट्रपति इस बात पर सहमत थे कि विकासशील देशों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से स्पट करने के लिए विश्व व्यापार संगठन से जुड़े मुद्दों पर एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन बनाने, जी-15 जैसे समूहों में प्रभावी सहयोग बढ़ाने और संयुक्त राट्र को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

जी-8 देशों की विस्तृत वार्ता विकसित और विकासशील देशों के बीच उच्चतम स्तर पर संपर्क बनाने का एक उपयोगी मंच बन सकती है। एवियान में पधारे कई प्र ातिभागियों ने यह विचार प्रकट किया कि भविय में जी-8 की अध्यक्षता करने वाले देश इस पहल को जारी रखें।

मैंने प्रधानमंत्री वन ज्याबाओ के निमंत्रण पर इस र्वा 22 से 27 जून तक चीन की यात्रा की । लगभग दस र्वा के बाद भारत के प्रधानमंत्री की यह चीन की पहली यात्रा थी । इस यात्रा से मुझे चीन के नए नेतृत्व के साथ व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करने का अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ । चीन में मेरा बडी गर्मजोशी और शालीनता के साथ स्वागत किया गया तथा मुझे इस बात का विशिट रूप से एहसास दिलाया गया कि वे भी हमारी तरह परस्पर सद्भाव बनाने तथा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में विविधता लाने के लिये पूरी तरह इच्छुक हैं । मेरी सभी बैठकों के दौरान आपसी विश्वास और समझ-बूझ पैदा करने की चल रही प्रक्रिया को मजबूत करने की दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दोहराया गया ।

हमने दस समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनकी सूची सदन के पटल पर रखी गई है । भारत-चीन संबंधों में पहली बार दो प्रधान मंत्रियों द्वारा एक संयुक्त घोाणा -पत्र पर हस्ताक्षर किये गये । संयुक्त घोाणा-पत्र संलग्न है तथा सदन के पटल पर रखा गया है । इस धोाणा-पत्र में उन सिद्धांतों और समान विचारों का उल्लेख किया गया है जिनसे हमारे द्विपक्षीय संबंधों में भावी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इसमें बहुध्रुवता की ओर बढ़ते हुए रुख को मजबूत करने के लिए, विश्व व्यापार संगठन संबंधी मुद्दों पर और विकासशील देशों की चिंताओं पर हमारे दोनों देशों को अंतर्राट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता की भी पुटि की गई है।

यह घोाणा-पत्र भारत चीन सीमा प्रश्न के समाधान को दोनों देशों द्वारा दिए गए महत्व को परिलक्षित करता है। इस प्रश्न के अंतिम हल के सिद्धान्तों पर कुछ समय से विचार-विमर्श चल रहा है। प्रधान मंत्री वन ज्याबाओ और मैं इस बात पर सहमत हुए कि समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में सीमा समाधान के ढांचे की खोज के जरिए इन चर्चाें को एक नई गति प्रदान की जानी चाहिए। हमने इस प्रयोजन के लिए विशे प्रतिनिधि नियुक्त किए हैं। राट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे विशे प्र ातिनिधि होंगे। चीन ने अपनी ओर से अपने सबसे वरिठ उप-विदेश मंत्री को नियुक्त किया है। प्रधान मंत्री वन ज्याबाओ तथा मैं इस बात पर भी सहमत हुए कि वास्तविक नियन्त्रण रेखा के स्पटीकरण से संबंधित संयुक्त कार्य सहज रूप से जारी रहे तथा सीमा क्षेत्रों में बनी शांति और अमन-चैन को बरकरार रखा जाए।

हमारे द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर विशे बल दिया गया। मेरी यात्रा के दौरान चीन में सी.आई.आई. फिक्की तथा एसोचम (ASSOCHAM) के वरिठ व्यावसायियों का एक बड़ा शिटमंडल मौजूद था। मैंने बीजिंग तथा शंघाई में भारत और चीन के व्यावसायियों की दो बैठकों को संबोधित किया, जिनमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री बीजिंग में चीन के सम्बद्ध मंत्रियों से मिले। उन्होंने संबंधित एजेंसियों तथा चीन के व्यावसायियों के साथ भी गहन विचार-विर्मा किया। हमारे संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिवेश मंत्री ने भी इसी तरह शंघाई में उपयोगी बातचीत की।

दोनों ही पक्ष हमारे आर्थिक संबंधों की क्षमता से भली-भांति अवगत थे। यह द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में संभावित प्रतिपूरक पहलुओं का पता लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन दल गठित करने के निर्णय में परिलक्षित हुई। यह संयुक्त अध्ययन दल दोनों देशों की सरकारों को व्यापार बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहन देने तथा हमारे व्यापार समुदायों के बीच अधिक से अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस उपायों की सिफारिश करेगा। हमने आर्थिक संवाद एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया जिससे इस क्षेत्र में हमारा समन्वय मजबूत हो।

एक और महत्वपूर्ण बात यह रही कि भारत-चीन सीमा पर नाथूला दर्रे से सीमा व्यापार संबंधी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार के लिए एक तीसरा सीमा दर्रा नियुक्त हो गया है। इस ज्ञापन के साथ ही हमने एक ऐसी प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है, जिससे भविय में भारत-चीन संबंधों में सिक्किम एक मुद्दा नहीं रहेगा।

तिब्बत के संबंध में, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी दशकों पुरानी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। हमने कभी भी इस बात पर सन्देह व्यक्त नहीं किया कि तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र चीन गणराज्य की भूमि का हिस्सा है। इसलिए, इसे दोहराने के विरुद्ध कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। हमने श्रद्धेय दलाईलामा अथाव तिब्बती शरणार्थियों की भारत में उपस्थिति के बारे में कोई नई बात नहीं कही है।

मेरी यात्रा के दौरान हमारे सांस्कृतिक संबंधों को भी नए सिरे से बढ़ावा मिला। हम दिल्ली और बीजिंग में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। मैंने बीजिंग विश्वविद्यालय में एक भारतीय अध्ययन केन्द्र का उद्घाटन किया तथा इस केन्द्र को चलाने के लिए भारत की ओर से कुछ अंशदान देने की घोाणा की। हमने अगले र्वा पंचशील, जो कि भारत-चीन संबंधों की एक आधारशिला है, की 50वीं र्वागांठ मनाने पर सहमति व्यक्त की है। मुझे लोयांग में व्हाइट हार्स टेम्पल जाने का सुअवसर मिला जो भारत से चीन आने वाले प्रथम बौद्ध भिक्षुओं के आगमन का प्रतीक है तथा जो हमारे संबंधों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आयाम को रेखांकित करता है। चीनी पक्ष कैलाश मानसरोवर यात्रा हेतु अतिरिक्त मार्ग खोलने के मेरे सुझाव पर विचार करने पर भी सहमत हुआ है।

मेरी यात्रा के दो उद्देश्य पूरे हो गए - चीन के नए नेतृत्व के साथ घनिठ संबंध स्थापित करना, और हमारे विविध द्विपक्षीय सहयोग को नई गति प्रदान करना। हम चीन से इस बात पर सहमत हैं कि हम सौहार्दपूर्ण चर्चाओं के जरिए अपने मतभेदों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर लाभदायक संबंध बनाए रखेंगे।

मैं इन सभी यात्राओं के नतीजों से संतुट हूं। जर्मनी के साथ हमारी वार्ता सुदृढ़ हुई है। राट्रपति पुतिन एक बड़े बहुपक्षीय कार्यक्रम के मेजबान के रूप में अपनी व्यस्तताओं के बावजूद पहले ही दिन आधी रात के बाद मेरे साथ द्विपक्षीय बैठक करने के लिए आए। यह इस बात का सूचक है कि वे हमारे द्विपक्षीय संबंधों को कितना महत्व देते हैं। राट्रपति शिराक ने जी-8 विस्तृत वार्ता का इस ढंग से संचालन किया, जिससे विकासशील देश होने के नाते हमारे विचारों का मूल महत्व उजागर हुआ। चीन के साथ आपसी विश्वास और समझ-बूझ बढ़ाने की दिशा में प्रगति हुई है।

जिन नेताओं से भी मैं मिला, सभी ने स्वाभाविक रूप से दक्षिण एशिया की स्थिति में रुचि दिखायी। मुझे यह देख कर खुशी हुई कि हमने पाकिस्तान की ओर मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है, उसका सभी नेताओं ने समर्थन किया और सराहना की तथा यह आशा व्यक्त की कि पाकिस्तान भी इसका प्रत्युत्तर देगा। सभी ने आतंकवाद के खतरे की कड़े शब्दों में निन्दा की। मैं यह समझता हूं कि मेरे वार्ताकार क्षेत्रीय और अन्तर्राट्रीय स्तर पर शांति को बढ़ावा देने की हमारी नीति को पूरी तरह से समझते हैं।

(Also Placed in Library, See No. LT. 7802/2003)

MR. SPEAKER : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on 24th July, 2003.

1830 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, July 24, 2003/ Sravana 2, 1925 (Saka).-------------------